

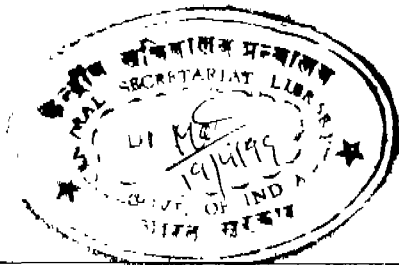


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 278]
No. 278]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, दिसम्बर 24, 1998/पौष 3, 1920
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 1998/PAUSA 3, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

(पाटनरोधी तथा सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1998

अंतिम जांच परिणाम

विषय : जापान, पुर्तगाल, स्पेन तथा इटली से एक्रोलिक फाइबर के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच—अंतिम जांच परिणाम।

32/1/97-ए डी डी.—1975 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (डम्प की गई वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को देखते हुए :

(क) प्रक्रिया

1. प्रारंभिक जांच-परिणाम के बाद जांच के संबंध में निम्नलिखित क्रिया विधि का पालन किया गया है :—

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकारी कहा जाएगा) ने जापान, पुर्तगाल, स्पेन तथा इटली से एक्रोलिक फाइबर के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच दिनांक 20-10-1998 की अधिसूचना द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम को अधिसूचित किया और हितबद्ध पक्षों से अनुरोध किया कि इसके प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप से अपने विचार भिजवा दें।
- (ii) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्ष की प्रति भिजवाई जिनसे अनुरोध किया गया कि इस पत्र की तारीख के चालीस दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अगर उनके कोई विचार हों, तो उन्हें भिजवा दिया जाए।
- (iii) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्ष की एक-एक प्रति जापान, पुर्तगाल, स्पेन तथा इटली के नई दिल्ली स्थित दूतावासों को भी इस अनुरोध के साथ भिजवाई कि निर्यातकों और अन्य इच्छुक पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्ष के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी जाए।
- (iv) प्राधिकारी ने सभी इच्छुक पार्टियों को 3-12-1998 को मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मौखिक विचार व्यक्त करने वाली सभी पार्टियों से अनुरोध किया गया कि मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए। पार्टियों को सलाह दी गई कि वे विरोधी पक्ष द्वारा प्रकट किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त कर लें और उनका खंडन, अगर कोई हो, प्रस्तुत करें।

- (v) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा तर्कों के गैर-गोपनीय अंश इच्छुक पक्षों को देखने के लिए उपलब्ध कराए जिन्हें सार्वजनिक फाइलों के रूप में रखा गया था।
- (vi) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा करने से पूर्व हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों, जिन्हें प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया गया, उन्हें संक्षिप्तता की दृष्टि से दोहराया नहीं गया है। तथापि हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर प्रारंभिक निष्कर्षों में और/या इन निष्कर्षों में समुचित रूप से विचार किया गया है।
- (vii) नियम 16 के अनुसार जिन आवश्यक तथ्यों/आधारों पर विचार किया गया उनकी जानकारी हितबद्ध पक्षों को दी गई थी और उसके बारे में प्राप्त टिप्पणियों पर इन निष्कर्षों में यथोचित रूप से विचार किया गया है।
- (viii) इस अधिसूचना में ×××× का चिह्न याचिकाकर्ता द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को प्रदर्शित करता है और नियमों के अन्तर्गत प्राधिकारी ने उसे गोपनीय ही माना है।

(ख) विचाराधीन उत्पाद

2. इसमें शामिल उत्पाद सिकुड़ने वाला तथा नहीं सिकुड़ने वाला दोनों किस्म का 1.5 डेनियर से 8.0 डेनियर तक का एक्रिलिक फाइबर है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क कोट 5501.30 तथा 5503.30 के अधीन वर्गीकृत है। एक्रिलिक फाइबर उनका एक किफायती विकल्प है। एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन गोली प्रौद्योगिकी अथवा शुष्क प्रौद्योगिकी के जरिए किया जाता है। एक्रिलिक फाइबर का दैनिक जीवन में उपयोग होता है अर्थात् अवरल, धरतू उपयोग के उत्पादों में तथा इसके कुछ औद्योगिक उपयोग भी हैं।

याचिकाकर्ता द्वारा तर्क

3. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि टो और टॉप केवल एक्रिलिक फाइबर हैं। यदि फाइबर को लम्बाई 2.0 मीटर है तो वह टो कहलाता है। यदि इसकी लम्बाई 2.0 मीटर से कम अर्थात्- अलग है तो वह स्टैपल फाइबर है। टो और स्टैपल दोनों का इस्तेमाल उपभोक्ता द्वारा उसी संयंत्र में और उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार स्टैपल फाइबर तथा टो दोनों का एक ही इस्तेमाल है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि यू.एस. कोरिया तथा थाईलैंड से पाटनरोधी जांच के पूर्ववर्ती मामले में टो, टॉप और स्टैपल पर भी शुल्क लगाए गए थे। निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई राजपत्रित अधिसूचना सार्वजनिक दस्तावेज है और इसके बारे में सम्मता उद्योग जगत जानता है। इस समय यह बहस करना कि किसी विशेष निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना केवल स्टैपल फाइबर के लिए है और उसमें टो शामिल नहीं है, इससे इस बात का राफ पता चलता है कि इस बारे में निर्यातकों में समझ की कमी है। अतः टो और टॉप को जांच के दायरे में शामिल किया गया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी को मौजूदा जांच के कार्य क्षेत्र के बारे में प्रारंभिक जांच निष्कर्षों की पुष्टि करनी चाहिए।

निर्यातक/आयातक द्वारा तर्क

4. निर्यातक/आयातक द्वारा तर्क दिया गया है कि टो पर शुल्क लगाने के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश क्षेत्राधिकार के बाहर, मनमानी तथा कानूनी रूप से गलत है। याचिकाकर्ता ने सीमाशुल्क कोड 5503.30 के अंतर्गत एक्रिलिक फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए याचिका दायर की थी और तदनुसार जांच शुरुआत की अधिसूचना जारी की गई थी। टो एक भिन्न वस्तु है जो टैरिफ प्रविष्टि 5501.30 के अंतर्गत आती है। टो जांच का विषय नहीं था। टो के विरुद्ध जांच शुरू न करके तथा बाद में टो पर शुल्क लगाकर, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने टो के संबंध में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं दिया। यही स्थिति टॉप के मामले में है। अतः इन्हें जांच के कार्य-क्षेत्र से निकाल दिया जाना चाहिए।

प्राधिकारी की स्थिति

5. प्राधिकारी सरकार द्वारा जारी किए गए 23 अप्रैल, 1998 के परिपत्र सं. 29 सी वी ई सी का हवाला देते हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि इस आशय की रिपोर्ट के आधार पर कि एक्रिलिक टो तथा टॉप को निकासी को पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना ही मांग की जा रही है, बोर्ड ने याचिका मंत्रालय के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया है कि एक्रिलिक टॉप तथा एक्रिलिक टो पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए और विगत में की गई निकासी, यदि कोई हो, तो इस स्पष्टीकरण के संदर्भ में भी उसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

6. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि टो को सीमाशुल्क प्रविष्टि सं. 5501.30 तथा एक्रिलिक फाइबर को प्रविष्टि सं. 5503.30 में वर्गीकृत किया गया है। जांच की शुरुआत के समय अधिसूचना में यह भी संकेत दिया गया था कि उक्त वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर किसी तरह के प्राधिकारी नहीं है। टो को फाइबर टो को एक्रिलिक फाइबर में कवर किया जा सकता है। कुछ निर्यातकों ने भी इस बात पर बहस किए गए बगैर बिना किसी एक अलग वस्तु है, प्रश्नावली का उत्तर देते समय तथा उसे प्रस्तुत करते समय टो संबंधी सूचना को भी शामिल किया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी टो, टॉप तथा स्टैपल फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है और इसे केन्द्रीय सरकार ने लगाया है। इसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने टो, टॉप तथा स्टैपल फाइबर पर शुल्क लगाने की सिफारिश को उचित माना है।

दिया गया तर्क

7. मै. असाही, जापान ने अनुरोध किया है कि यदि प्राधिकारी "ले" को जांच के क्षेत्र में शामिल करते हैं तो उनके द्वारा जांच के पश्चात् तथा प्रारंभिक जांच निष्कर्षों के बाद प्रस्तुत की गई सूचना को डंपिंग मार्जिन का निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए।

प्राधिकारी की स्थिति

8. टो और टॉप को डंपिंग मार्जिन का निर्धारण करने के लिए शामिल करने के असाही के तर्क के बारे में प्राधिकारी ने नोट किया है कि जांच शुरुआत के समय टो और टॉप के बारे में निर्यातक ने सूचना प्रस्तुत नहीं की थी और न ही सत्यापन के समय ही उन्हें जांच दल को उपलब्ध कराया। प्रारंभिक जांच निष्कर्षों के बाद प्रस्तुत की गई सूचना सत्यापित नहीं है। इसके अतिरिक्त इस चरण पर सूचना को खींचकर करना चम्बड देशों के अन्य सहयोगी निर्यातकों तथा याचिकाकर्ताओं के साथ अन्याय होगा। तथापि, निर्यातक अलग से सूचना फाइल करने के लिए तथा अलग से मर्यादित करने का अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र है।

दिया गया तर्क

9. मोड एक्रोलिक को जांच के क्षेत्र से निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें विचाराधीन उत्पाद के विवरण का उत्तर नहीं मिलता है। यह फाइबर भार के हिसाब से लगभग 50% एक्रिलोनीट्राइल इकाईयों से बना है जबकि एक्रोलिक फाइबर एक्रिलोनीट्राइल का 85% से अधिक का एक कोपोलीमर है। प्लेन रिटारडेंसी की अपनी अलग विशेषता के कारण मोड एक्रोलिक फाइबर का प्रतिस्थापन नहीं बन सकता है।

प्राधिकारी की स्थिति

10. प्राधिकारी निर्यातक के तर्क से सहमत है। याचिकाकर्ता ने निर्यातक के दावे पर कोई आपत्ति नहीं की है। याचिकाकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि भारतीय उद्योग जगत इस समय मोड एक्रोलिक (स्वतः सम्पन्न) फाइबर का निर्माण नहीं कर रहा है। इस दृष्टि से प्राधिकारी ने जांच के कार्य क्षेत्र से मोड एक्रोलिक फाइबर को निकाल दिया है।

(ग) समान वस्तु

11. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बेचे जाने वाले एक्रोलिक फाइबर में जापान, पुर्तगाल, स्पेन तथा इटली से आयातित एक्रोलिक फाइबर से बिल्कुल मिलती जुलती विशेषताएं हैं और इसलिए पाटनरोधी नियमों में दी गई परिभाषा के अनुसार इसे समान वस्तु के रूप में माना जाता है।

निर्यातक/आयातक द्वारा दिया गया तर्क

12. समान वस्तु पर निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा दिए गए तर्क निम्नानुसार हैं :—

(क) जी के तथा के 75 विशेष किस्म के फाइबर हैं जिसमें औद्योगिक प्रौद्योगिकी होती है जो भारत में उपलब्ध नहीं है। जी के तथा के 75 किस्म के स्पेशल्टी/फाइबर विनिर्माण प्रक्रिया अलग-अलग है। इनके अन्य प्रयोग को प्रतिस्पर्धित नहीं किया जा सकता। इन फाइबर्स को जांच के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

(ख) एल-2, लो थ्रिंक, वी 86 और वी 85 मोडोफाईड स्पेशल सरफेस फिनिश कंजुगेट/बाई कंपोनेट फाइबर, एन 525 अन्य स्पेशल्टी फाइबर है जिन्हें होने के कारण जांच के कार्यक्षेत्र से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि ये समान वस्तु नहीं हैं।

याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया तर्क

13. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि स्पेशल्टी फाइबर को शामिल न करने के बारे में निर्यातक का दावा ठीक नहीं है क्योंकि भारतीय उद्योग के पास सभी प्रकार के फाइबर का उत्पादन करने की क्षमता, तकनोलोजी संयंत्र तथा उपकरण मौजूद हैं। भारतीय उद्योग के पास मोड एक्रोलिक (स्वतः ज्वलनशील), वी 76 मोहेर तथा वी 86 को छोड़कर सभी प्रकार के एक्रोलिक का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस है। आई पी सी एल कंजुगेट फाइबर सहित सभी किस्म का फाइबर बना रहा है। कन्सोलिडेटेड फाइबर एण्ड कैमिकल्स के पास ऐसे सभी प्रकार के फाइबर का उत्पादन करने का लाइसेंस है। जो एक्सलन-टोयोचो उत्पादन कर सकता है। पशुपति एक्रिलोन इटली की स्नी से लाइसेंस लेकर फाइबर का उत्पादन कर रहा है। इंडियन एक्रोलिक यू एम ए से डूपोंट तकनोलोजी द्वारा फाइबर का उत्पादन कर रहा है और सभी प्रकार के फाइबर का उत्पादन करता है।

प्राधिकारी की स्थिति

14. स्पेशल्टी फाइबर कंजुगेट फाइबर को बाहर करने के बारे में प्राधिकारी ने नोट किया है कि निर्यातकों का यह दावा कि घरेलू उद्योग के पास इन फाइबर्स का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी और संयंत्र तथा उपकरण नहीं है। वस्तुतः सही नहीं है।

आई पी सी एल के पास प्रौद्योगिकी और संयंत्र एवं उपकरण दोनों हैं। इसके अलावा, इस बात से इन्कार नहीं किया गया है कि आई पी सी एल इन फाइबरों का उत्पादन करता रहा है। इस बात का भी कोई महत्व नहीं है कि इनका उत्पादन नम प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

या शुल्क प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए क्योंकि उससे यदि कोई अन्तर आता है तो उसके बारे में कोई प्रमाण भी नहीं दिया गया है। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक भारतीय उत्पादक ऐसा फाइबर बनाता हो। केवल इसी आधार पर निर्यातकों के दावे को अस्वीकृत किया जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित अन्य फाइबर तथा संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उन विशेष फाइबरों का भी उपभोक्ताओं द्वारा उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निर्यातक सामान्य फाइबर की तुलना में इन वस्तुओं की कीमत निर्धारण के आधार पर अपने दावे की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जिन कीमतों पर भारत को माल का निर्यात किया गया उनके ब्यौरे से निर्यातकों के इस दावे की पुष्टि नहीं होती है कि वे स्पेशल फाइबर हैं, क्योंकि सामान्य फाइबर तथा विशेष फाइबर की कीमत एक जैसी ही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि ये विशेष फाइबर हैं, तो भारतीय बाजार में इनकी ऊँची कीमत मिलनी चाहिए थी। अतः प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बेचे जाने वाले एक्रिलिक फाइबर की विशेषताएं जापान, पुर्तगाल, स्पेन तथा इटली से आयातित एक्रिलिक फाइबर से बिल्कुल मिलती-जुलती हैं और नियमों के अन्तर्गत उन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए।

(घ) घरेलू उद्योग

15. मैसर्स इंडियन एक्रोलिक्स लि. खंडीगढ़, पशुपति एक्रिलोन लि. नई दिल्ली, जे के सिंथेटिक लि., नई दिल्ली तथा कंसोलीडेटेड फाइबर एण्ड कैमिकल्स लि. कलकत्ता ने संयुक्त रूप से याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इंडियन पैट्रोकेमिकल्स लि., जिनका संयंत्र बड़ोदरा में है, एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन करने वाली अन्य कंपनी है। अतः यह दावा किया गया है कि ये पांच इकाइयां हैं जो एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन करती हैं जिनकी सामूहिक क्षमता 1,02,000 मी. टन है। 1996-97 एक्रिलिक फाइबर का कुल उत्पादन 79,000 मी. टन बतलाया गया है और याचिकाकर्ता कंपनियों का कुल उत्पादन 61187 मी. टन है। याचिका को "फोरम ऑफ एक्रिलिक फाइबर मैनुफैक्चर्स" का समर्थन प्राप्त है और सभी पांच कंपनियां फोरम ऑफ एक्रिलिक फाइबर मैनुफैक्चर्स के सदस्य हैं। अतः याचिकाकर्ता का घरेलू उत्पादन में 25% से अधिक हिस्सा है। अतः नियमों के तहत घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की स्थिति में है। किसी भी हितबद्ध पक्ष ने याचिका को दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं की स्थिति के बारे में कोई तर्क नहीं किया है। अतः प्राधिकारी इस आशय के प्रारंभिक जांच निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं कि याचिकाकर्ता का घरेलू उत्पादन में 25% से अधिक हिस्सा है और इसलिए नियमों के तहत घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का हकदार है।

(ङ) घाटन

निर्यातक का तर्क

16. मैसर्स कनेका कारपोरेशन, मित्सुई एंड कंपनी तथा कनेमत्सु कारपोरेशन जापान ने निर्यातक द्वारा विचार प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख के बाद उत्तर दिया। इन पर प्रारंभिक जांच निष्कर्षों में विचार नहीं किया गया था। निर्यातक ने अनुरोध किया है कि इन पर अब विचार किया जाए।

प्राधिकारी की स्थिति

17. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि कनेका कारपोरेशन का दावा है कि वे केवल कनेकेशन ब्रांड तथा प्रोटेक्स ब्रांड वाले मोड एक्रिलिक फाइबर का ही उत्पादन करते हैं तथा इसका मित्सुई एंड कंपनी तथा कनेमत्सु कारपोरेशन के माध्यम से भारत को निर्यात करते हैं। यह दावा भी किया गया है कि उनकी जानकारी के अनुसार भारत में मोड एक्रिलिक फाइबर अथवा इसके समान उत्पाद का कोई उत्पादन नहीं होता है तथा इसलिए घरेलू उद्योग को कोई क्षति होनी नहीं चाहिए। प्राधिकारी ने "विचाराधीन उत्पाद" पर अनुच्छेद में पहले ही यह निर्णय लिया है कि मोड एक्रिलिक फाइबर (स्वतः ज्वलनशील) को जांच के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा जाए तथा इसलिए प्राधिकारी ने मोड एक्रिलिक फाइबर से संबंधित उपरोक्त निर्यातकों के दावे की जांच नहीं की है।

याचिकाकर्ता के तर्क

निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित डम्पिंग मार्जिन याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध जानकारी की तुलना में बहुत ही कम है।

प्राधिकारी की स्थिति

19. प्राधिकारी द्वारा डम्पिंग मार्जिन निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रारंभिक जांच परिणामों में दी गयी है। डम्पिंग मार्जिन निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित है, जिनकी प्राधिकारी द्वारा जहाँ तक उचित समझा गया, जांच की गयी है। याचिकाकर्ता ने न तो प्राधिकारी द्वारा डम्पिंग मार्जिन के आकलन की प्रक्रिया पर विवाद किया है और न ही सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध उन तथ्यों तथा आंकड़ों पर आपत्ति की है जो कि निर्यातकों द्वारा दिये गये थे। अतः याचिकाकर्ता का यह तर्क कि डम्पिंग मार्जिन उनके पास उपलब्ध सूचना की तुलना में बहुत कम है, सामान्य स्वरूप का है तथा इसके तथ्यों के जरिए प्रमाणित नहीं किया गया है।

दिए गए तर्क

20. प्राधिकारी द्वारा डम्पिंग मार्जिन की गणना, ग्रेड/डेनियर वार की जानी चाहिए जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से एक्रिलिक फाइबर के आयात के अन्य मामले में की गयी है।

प्राधिकारी की स्थिति

21. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुच्छेद 11 में यह निर्णय लिया था कि प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह पाया गया है कि एकीकृत फाइबर के विभिन्न डेनियर लागत अथवा कीमतों के रूप में कोई महत्वपूर्ण अंतर प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा वे एक जैसी रेंज में रहती हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न किस्मों के बीच अत्यधिक प्रतिस्थापन क्षमता है तथा इसलिए प्राधिकारी ने सभी फाइबरों (विचाराधीन उत्पाद के रूप में उल्लिखित) को इस जांच के लिए इकट्ठा कर दिया। प्राधिकारी ने यह बात नोट की है कि किसी भी हितबद्ध पक्ष ने प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 11 में दिए गए प्राधिकारी के इस अभिमत का खंडन नहीं किया है। किसी भी हितबद्ध पक्ष ने इस बात का प्रमाण नहीं दिया है कि विभिन्न डेनियर लागत अथवा कीमत के रूप में कोई महत्वपूर्ण अंतर प्रदर्शित करते हैं अथवा यह कि वे एक ही रेंज में नहीं हैं अथवा यह कि विभिन्न किस्मों के बीच कोई प्रतिस्थापितता नहीं है। अतः प्राधिकारी ने अपने पहले के निर्णय को बरकरार रखते हुए सभी फाइबरों (विचाराधीन उत्पाद के रूप में उल्लिखित) को इस जांच के लिए इकट्ठा किया है।

दिया गया तर्क

22. निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारण करते समय प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच में कुछ समायोजनों की अनुमति नहीं दी गयी है। इनकी अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने समायोजनों की अनुमति न देकर ठीक किया है।

प्राधिकारी की स्थिति

23. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच में विस्तार से समायोजनों पर विचार किया है। प्राधिकारी द्वारा दिए गए विभिन्न समायोजनों पर किसी भी हितबद्ध पक्ष ने कोई विवाद नहीं किया है। तथापि, निर्यातकों ने उन समायोजनों पर तर्क किया है जिनकी अनुमति नहीं दी गई है। समायोजनों को अस्वीकार करते हुए प्राधिकारी ने दावों को स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों का खुलासा किया है।

24. निर्यातक-वार दावों पर निम्नानुसार पुनर्विचार किया गया है :—

श. असाही कैमिकल इंडस्ट्रीस लि., जापान

25. कम्पनी द्वारा रखे गए माल के आधार पर भण्डारण लागत के लिए किए गए समायोजन के दावे को प्रारंभिक जांच परिणामों में अनुमति नहीं दी गयी थी। निर्यातक ने प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद स्पष्ट किया था कि भण्डारण लागत वस्तुओं के घरेलू बाजार में बेचे जाने से पहले माल गोदाम में रखे जाने की लागत है। इन लागतों का भुगतान बाह्य मालगोदाम कम्पनियों को किया जाता है। ये वस्तुएं विभिन्न मालगोदामों से विभिन्न उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं। प्राधिकारी ने इस प्रकार के किसी भी खर्च की अनुमति प्रदान नहीं करने की लगातार प्रक्रिया अपनायी है। इस को देखते हुए, प्राधिकारी इस कारण किसी भी खर्च की अनुमति प्रदान नहीं करना उचित समझते हैं। चूंकि जापान से निर्यात येन में हुआ था, इसलिए निर्यातक ने दावा किया है कि प्राधिकारी को येन की रु. के साथ विनिमय दर को अपनाना चाहिए न कि अमरीकी डालर के साथ येन की तथा रु. के साथ अमरीकी डालर की विनिमय दर को। यह देखा गया है कि प्रारंभिक जांच परिणाम के समय प्राधिकारी ने येन से अमरीकी डालर तथा अमरीकी डालर से रुपए में विनिमय को अपनाया है क्योंकि निर्यातकों ने सूचना तदनुसार ही प्रस्तुत की थी। फिर भी, चूंकि निर्यातकों ने अब येन से रुपए में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया है, इसलिए प्राधिकारी ने उसी को अपनाया है।

26. प्रारंभिक जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने टर्न ओवर तथा अंतिम उपभोग के आधार पर छूटों के कारण किए गए दावे की अनुमति प्रदान नहीं की क्योंकि मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय लेते समय ऐसी छूट/बट्टे का प्रभाव का सुनिश्चय नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि क्या भुगतान के लिए दोनों मूल्यों का निर्धारण तथा उनके बारे में सहमति अनुबंध करते समय होती है। वास्तव में अनुबंध करते समय केवल वे शर्तें ही मालूम होती हैं जिनके अंतर्गत ऐसे भुगतान देय होते हैं। वास्तविक देय राशि का पता केवल संबंधित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् ही चलता है और यह अधिकतर इस अवधि के दौरान कुछ शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करता है। यह तथ्य कि केवल इन शर्तों को पूरा करने वाले उपभोक्ता ही राशि प्राप्त करने के पात्र हैं, यह प्रमाणित करता है कि कम्पनी द्वारा देय पूरी राशि अवधि की शुरुआत में कंपनी को ज्ञात नहीं होती है, जो कि दोनों बाजारों में खर्चों में अंतर के कारण कीमत समायोजन के दावे की एक आवश्यक शर्त है। इसको ध्यान में रखते हुए, दावे को अनुमति नहीं दी जाती है।

27. इसे देखते हुए प्राधिकारी ने डमिंग मार्जिन का पुनः निर्धारण किया है और वह निर्यात मूल्य का 18.26% आता है। चूंकि प्राधिकारी ने असाही के मामले में येन से रुपए में विनिमय पर विचार किया है, इसलिए प्राधिकारी इसे उचित मानते हैं कि जापान ने अन्य उत्पादकों के मामले में भी वही विनिमय दर अपनाई जाए। तदनुसार, मित्सुबिशी तथा टोयोबो के मामले में डमिंग मार्जिन का निर्धारण किया गया। संशोधित डमिंग मार्जिन क्रमशः 11.30% तथा 5.92% आता है।

II. मोटे फाइबर इटली

28. मोटे फाइबर के मामले में डंपिंग का निर्धारण निम्नानुसार है :

(क) शीघ्र भुगतान तथा गुणवत्ता छूट के लिए 2% का दावा अनुमानों के आधार पर किया गया है। यह दावा किया गया है कि इसमें 1% से 4% तक उतार-चढ़ाव होता है तथा इसलिए कटौती का दावा करने के लिए औसतन 2% का उपयोग किया जाता है। प्राधिकारी ने इस दावे को इसलिए अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि यह अनुमानों पर आधारित था। अब यह अनुरोध किया गया है कि क्योंकि न्यूनतम छूट 1% थी, इसलिए इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। प्राधिकारी इस तर्क से सहमत हैं तथा न्यूनतम 1% त्वरित भुगतान तथा गुणवत्ता छूट की अनुमति दी जाती है।

(ख) अनुसंधान एवं विकास संवर्धन तथा विज्ञापन के कारण किए गए दावे को अस्वीकृत किया गया था क्योंकि प्राधिकारी ऐसे साक्ष्य के अभाव में, जिसमें इस बात की पुष्टि होती हो कि इन कार्यकलापों से प्राप्त लाभ केवल घरेलू बिक्री तक ही सीमित रहा है, इन खर्चों की अनुमति प्रदान करना औचित्यपूर्ण नहीं मानते हैं। निर्यातक ने अनुसंधान एवं विकास संबंधी लागत, तकनीकी सेवाओं तथा संवर्धन के आधार पर दावे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है क्योंकि यह केवल घरेलू बाजार में बेचे गए फाइबरों के संबंध में है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा दावे को प्रारंभिक निष्कर्षों में पहले से दिये गये कारणों की वजह से अस्वीकृत किया जाता है।

(ग) सत्यापन के दौरान निर्यातक ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय भारतीय एजेंट का भुगतान किये गए भारत औसत कमीशन के बराबर कटौती की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था। प्राधिकारी ने सत्यापन के लिए किए गए दौरों के समय पर भी निर्यातक द्वारा कोई सबूत प्रस्तुत न कर पाने के कारण उक्त दावे को अस्वीकृत कर दिया था। उन्होंने इस आधार पर दावे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है कि भारत को निर्यात, एजेंटों के माध्यम से किया जाता है जबकि घरेलू बाजार में बिक्रियां सीधे ही की गयी थीं और इस प्रकार, व्यापार के स्तर में भिन्नता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए प्रारंभिक निष्कर्षों में दिए गये कारणों की वजह से दावे को अस्वीकार किया जाता है।

29. उपरोक्त को देखते हुए, पाटन मार्जिन को निर्यात कीमत के 22.90% तक संशोधित किया जाता है।

III. कोर्टलाईस एस्पना, एस ए, स्पेन

सत्यापन के दौरान निर्यातक ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय भारतीय एजेंट को भुगतान किये गए भारत औसत कमीशन के बराबर कटौती की अनुमति देने का अनुरोध किया था। प्राधिकारी ने सत्यापन के संबंध में किए गए दौरों के समय पर भी निर्यातक द्वारा कोई सबूत प्रस्तुत न कर पाने के कारण उक्त दावे को अस्वीकृत कर दिया था। निर्यातक ने अब इस आधार पर दावे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है कि भारत को होने वाला निर्यात एजेंटों के माध्यम से किया जाता है। जबकि घरेलू बाजार में बिक्री सीधे ही की गयी थी और इसलिए व्यापार के स्तर में भिन्नता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए प्रारंभिक निष्कर्षों में पहले ही दिए गए कारणों की वजह से दावे को अस्वीकार किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक निष्कर्षों में दिए गए पाटन मार्जिन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

IV. पिसाइप पुर्तगाल

31. भण्डारण शुल्कों के दावे की स्वीकृति नहीं दी गयी थी। यह दावा कम्पनी के पास पड़े बेशी माल के आधार पर भंडारण लागत के लिए किया गया था। निर्यातक ने इस दावे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है क्योंकि प्राधिकारी ने इस दावे को अस्वीकृत करने का कोई कारण नहीं बताया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दावा बेशी माल के संबंध में किया गया था जो निर्यातक ने घरेलू बाजार में बिक्री के प्रयोजन से रखा हुआ है। यह दावा अनुमानों के आधार पर किया गया है और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया है। इसे देखते हुए प्रारंभिक जांच परिणामों में यथा वर्णित पाटनसीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

32. उपर्युक्त को छोड़कर, प्राधिकारी संयुक्त देशों के दूसरे निर्यातकों के संबंध में पाटन और पाटन मार्जिन के मामले में प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

(च) क्षति और कारणात्मक संबंध

33. याचिका कर्ता का तर्क : याचिकाकर्ता को क्षति निम्नलिखित कारणों से हुई है :

- (क) संयुक्त देशों से आयातों में वृद्धि।
- (ख) सभी देशों से समग्र रूप से आयातों में वृद्धि।
- (ग) आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में कमी।
- (घ) 100% क्षमता उपयोग के बावजूद क्षति।
- (ङ) अर्धशेष स्टॉक में वृद्धि।
- (च) आयातों के कारण मूल्य में कटौती।
- (छ) निधियों एकत्र करने में असमर्थता।

(ज) फाइबर के नए प्रयोग का विकास करने के लिए आर एंड डी क्रियाकलापों में असमर्थता।

निर्यातक/आयातक द्वारा दिए गए तर्क

34. निम्नलिखित तथ्यों को देखते हुए घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है :—
 - (क) जांच अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री में वृद्धि हुई है;
 - (ख) उत्पादन लागत में कमी के कारण बिक्रय मूल्य गिर गया है;
 - (ग) याचिकाकर्ता की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है और घाटे में चल रहे एककों में मुनाफा कमना शुरू कर दिया है;
 - (घ) विस्तार योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है।
 - (ङ) मांग में वृद्धि के कारण बाजार भागीदारों में गिरावट आई है जिसका घरेलू उद्योग उत्पादन करने में असमर्थ है।
 - (च) माल स्टॉक में कथित वृद्धि माल सूचियों में से एक सबसे छोटी माल सूची है।
 - (छ) जे. के. सिन्थेटिक को उनकी अंदरूनी समस्याओं के कारण क्षति विश्लेषण के पथोजन में छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि कथित पाटन के बारे में उन्हें कुछ नहीं करना है।
 - (ज) कीमतों में गिरावट का श्रेय अलग-अलग रूप से दूसरे देशों से किए गए आयातों को जाता है।

प्राधिकारी की स्थिति

35. यह सराहनीय है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री का मात्रा इत्यादि में वृद्धि हुई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी संबंध पैमाने जरूरी नहीं कि क्षति की पुष्टि करते हों। जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणामों में क्षति पर निष्कर्ष से संबंधित पैरा 'ढ' में भी प्राधिकारी ने उल्लेख किया है, घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति को प्रमाणित करने वाले कारकों में यह हैं जैसे कि संबंध देशों से आयातों को मात्रा में समग्र रूप से और भारत में एक्रोलिक फाइबर की खपत के मापेक्ष में वृद्धि हुई है, याचिकाकर्ता कंपनियों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। उचित मूल्य पर बिक्री करने में घरेलू उद्योग की असफलता संबंध देशों से आयात के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को कम करना, घरेलू उद्योग के अधिशेष स्टॉक में वृद्धि, घरेलू उद्योग द्वारा घाटा उठाना इत्यादि। कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण बिक्री कीमतों में कमी के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि कच्चे माल की कीमतों को कारण बिक्री मूल्यों में गिरावट आई होगी फिर भी यह सत्य है कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त लाभ कमाने से रोकित रखा गया था और इस पर कोई विवाद नहीं है। घरेलू उद्योग के लिए उचित बिक्री मूल्य का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने चूंकि जे. के. सिन्थेटिक को अलग रखा है इसलिए जे. के. सिन्थेटिक की क्षमता को प्रभावित करने वाले पैमाने की अनदेखी को जानी चाहिए।

36. उपर्युक्त के आलोक में और सभी हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी ने पाया है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षति पाटन आयातों के कारण हुई है।

(छ) दूसरे तर्क

दिए गए तर्क

37. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जापान, पुर्तगाल, स्पेन और इटली के विरुद्ध जांच शुरू की है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के अनुरोध के अनुसार संपूर्ण यूरोपियन संघ के विरुद्ध जांच शुरू नहीं की है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपियन संघ के विरुद्ध मामला शुरू नहीं करने के लिए न तो जांच आरंभ करने की अधिसूचना में, कारणों का उल्लेख किया है और न ही प्रारंभिक जांच परिणामों में। यूरोपियन संघ के किसी सदस्य देश के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क तब तक प्रभावी नहीं हो सकता है जब तक सम्पूर्ण यूरोपियन संघ के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क न लगाया जाए। यूरोपियन संघ में कोई सीमाशुल्क अवरोध नहीं है। मलेशिया और इंडोनेशिया ने सम्पूर्ण यूरोपियन संघ के विरुद्ध शुल्क लगाया है।

प्राधिकारी की स्थिति

38. प्राधिकारी ने उन देशों के विरुद्ध जांच शुरू करने का निर्णय लिया है जिनके नाम याचिका में हैं और जिनके विरुद्ध सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बारे में विशेष सूचना दी गई थी। दायर याचिका में यह भी देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने पूरे यूरोपियन संघ के विरुद्ध भी जांच शुरू करने का अनुरोध किया था। तथापि अपने दिनांक 2-12-97 के पत्र के द्वारा याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के अलावा निम्नानुसार अनुरोध किया था :

“पाटन के बारे में कथित जांच की शुरुआत सामूहिक रूप के बजाय अलग-अलग शामिल देशों के विरुद्ध शुरू की जाए। तदनुसार हमारी याचिका पर आप विचार कर सकते हैं और जापान, पुर्तगाल, स्पेन और इटली के विरुद्ध जांच कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

39. तदनुसार प्राधिकारी ने इन विशेष देशों के विरुद्ध जांच शुरू की थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की यह दलील कि उन्होंने संपूर्ण यूरोपियन संघ के विरुद्ध जांच शुरू करने का अनुरोध किया था, वस्तुतः सही नहीं है। प्राधिकारी इतने विलम्ब से अब यूरोपियन संघ को शामिल करने के अनुरोध को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।

दिया गया तर्क

40. आयातों में वृद्धि, इति शेष स्टॉक में वृद्धि और बिक्री वसूलियों में कमी के कारण जांच पश्चात् अवधि में क्षति ज्यादा गंभीर है।

प्राधिकारी की स्थिति

41. प्राधिकारी ने जांच-पश्चात् अवधि के दौरान हुई क्षति को, अगर कोई है, तो उसे हिसाब में नहीं लिया है क्योंकि अन्य हितबद्ध पार्टियों को जांच-पश्चात् अवधि में हुई ऐसी क्षति के बारे में टिप्पणी करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है।

दिया गया तर्क

42. प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणामों में यह स्पष्ट करना चाहिए कि हालांकि बीजक एक व्यापार घराने से प्राप्त हुआ था, फिर भी पाटनरोधी शुल्क उत्पाद के विनिर्माता के आधार पर लगाया जाना चाहिए न कि उस व्यापार घराने पर जिसका नाम बीजक में है।

प्राधिकारी की स्थिति

43. व्यापार घरानों का अलग से मूल्यांकन करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन कंपनियों के स्वाभाविक स्वरूप के कारण ये किसी भी उत्पादनकर्ता के माल का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए इन व्यापार घरानों द्वारा की गई खरीद और बिक्री के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनायी जा सकती है। जांचकर्ता प्राधिकारियों की यह आम परिपाटी है कि अलग शुल्कों के लिए केवल उत्पादनकर्ताओं का ही मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा, अलग से मूल्यांकन नहीं होने के आधार पर व्यापार घरानों को व्यापार करने से रोका नहीं जाता है।

दिया गया तर्क:

44. जैसा कि निर्यातकों ने प्रतिवेदन किया है, संदर्भ मूल्य का निर्धारण करना पाटनरोधी शुल्क के विपरीत है ताकि पाटनरोधी शुल्क क्षति सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और मौजूदा मामले में संदर्भ मूल्य के संबंध में पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण करना भेदभावपूर्ण होगा जब इसकी तुलना दूसरे देशों के ऐसे निर्यातकों से की जाय जिनके विरुद्ध "निश्चित शुल्क" लगाए गए थे। याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जैसाकि प्रारंभिक जांच परिणामों के समय किया गया था, उसी प्रकार शुल्क की सिफारिशें परिवर्तनीय आधार पर की जानी चाहिए। निर्यातकों द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी को प्रत्येक निर्यातक के लिए निर्धारित की गई पाटन सीमा के बराबर उच्चतम शुल्क की शर्त पर न्यूनतम कीमत के लिए सिफारिश करनी चाहिए।

प्राधिकारी की स्थिति

45. प्राधिकारी कतिपय न्यूनतम शुल्कों की शर्त के साथ संदर्भ मूल्य रखते हुए परिवर्तनीय आधार पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश को उपयुक्त मानता है। प्राधिकारी यह नहीं मानते हैं कि अन्य देशों के निर्यातकों की तुलना में संस्तुत शुल्क भेदमूलक हैं।

46. किसी भी हितबद्ध पार्टी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि कतिपय न्यूनतम राशियों के प्रावधानों के साथ परिवर्तनीय शुल्कों की सिफारिशें नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल कैसे हैं। इसके अतिरिक्त किसी संभावित प्रवचना को रोकने के लिए इन न्यूनतम शुल्कों की सिफारिश करना अपेक्षित है। यदि किसी निर्यातक द्वारा यह महसूस किया जाता है कि चालू पाटन मार्जिन वसूल किए जा रहे शुल्क की अपेक्षा कम है तो ऐसी स्थिति में निर्यातक नियमों के अनुसार समीक्षा का अनुरोध कर सकता है।

दिया गया तर्क:

47. वैट स्पन तथा ड्राई स्पन फाइबर को एक समान मानना सही और उपयुक्त नहीं है क्योंकि इनका उत्पादन, प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण एवं अंतिम प्रयोग आदि सभी अलग-अलग हैं।

प्राधिकारी की स्थिति

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक्रिलिक फाइबर के उत्पादन की दो सुस्वीकृत तकनालाजी हैं—नम स्पन और शुष्क स्पन। कोई भी हितबद्ध पार्टी इन दोनों प्रौद्योगिकियों से उत्पादित फाइबर में किसी महत्वपूर्ण भिन्नता के बारे में सबूत के साथ इसे सिद्ध करने में समर्थ नहीं रही है। इसके अतिरिक्त बरेल्ट उद्योग दोनों प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए फाइबरों का उत्पादन करता है और इन दोनों प्रौद्योगिकियों को काम में लेकर उत्पादित फाइबर उपभेक्ताओं द्वारा अदल-बदल कर उपभोग किया जा रहा है।

उठाया गया मुद्दा

49. डी. जी. सी. आई. एस. सांख्यिकी दर्शाते हैं कि कथित रूप से पाटित आयातों की कीमतों के मुकाबले उन देशों से हुए आयातों की कीमतें कम हैं जो पाटन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार अन्य देशों से कम मूल्य पर आयातों के कारण जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती/दबाव, अगर कोई है, हुआ। ऐसे कम कीमत वाले आयातों की मात्रा भी महत्वपूर्ण है।

प्राधिकारी की स्थिति

50. प्राधिकारी ने पाया है कि जांच अवधि के दौरान एक्रिलिक फाइबर का कुल आयात 21114 मी. टन हुआ है। इसमें से जापान, पुर्तगाल, स्पेन और इटली जिन्होंने इस याचिका में कथित रूप से पाटन किया है, से आयात 9548 मी. टन हुआ था। शेष 11566 मी. टन में से 8727 मी. टन का आयात

यू. एस. ए., थाईलैंड एवं कोरिया से हुआ था जिनके विरुद्ध प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच शुरू की थी। यू. एस. ए., थाईलैंड एवं कोरिया से उक्त आयात भी कथित रूप से पाटित मूल्यों पर हुआ था। इस प्रकार जांच अवधि के दौरान अधिकांश आयात कथित रूप से पाटित मूल्यों पर हुआ था और इस प्रयोजन से उठाए गए तर्क वस्तुतः सही नहीं हैं।

51. यह देखा गया है कि कुछ निर्यातकों ने जांच अवधि के दौरान एक्रीलिक फाइबर का निर्यात न करने की बात कही है और इसलिए उनके उत्पाद/निर्यात पर कोई पाटनरोधी शुल्क न लगाया जाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि इन निर्यातकों ने जांच अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया है इसलिए वे नियम 22 के अंतर्गत आते हैं और तदनुसार वे अलग से मूल्यांकन के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

दिया गया तर्क

52. स्पेन के नई दिल्ली स्थित दूतावास ने दावा किया है कि स्पेनिश निर्यातों के स्तर के कारण स्पेन को इन पाटनरोधी उपायों से छूट दी जानी चाहिए। यह दावा किया गया है कि जांच अवधि के दौरान स्पेनिश निर्यात शून्य के बराबर प्रतीत होते हैं।

प्राधिकारी की स्थिति

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. कोर्टलॉद स्पेन, द्वारा प्रस्तुत आयात सांख्यिकी और सूचना के अनुसार स्पेन ने जांच अवधि के दौरान एक्रीलिक फाइबर का निर्यात किया है और इस प्रकार दूतावास का दावा वस्तुतः सही नहीं है।

छ. अंतिम जांच परिणाम

54. उपर्युक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि :—

(क) जापान, पुर्तगाल, स्पेन तथा इटली से एक्रीलिक फाइबर का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है, जिसके फलस्वरूप एक्रीलिक फाइबर का पाटन हुआ;

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(ग) डम्पिंग तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध प्रमाणित होता है।

55. प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने संबंधी प्रारंभिक जांच-परिणाम को पुष्टि करते हैं और जापान, स्पेन, पुर्तगाल तथा इटली मूल के या वहां से निर्यातित ऐसे एक्रीलिक फाइबर के सभी आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं जो कि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित पैरा में यथा विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क अधिनियम के सीमा-शुल्क उपशीर्ष सं. 5501.30 और 5503.30 के अन्तर्गत आता है। यह पाटनरोधी शुल्क कालम 4 में उल्लिखित राशि और आयातों की प्रति कि. ग्रा. पहुंच कीमत के अंतर के बराबर होगा, धराते कि प्रति कि. ग्रा. न्यूनतम पाटनरोधी शुल्क नौवें कालम 5 में दर्शाए गए अनुसार होगा।

क्रमांक	देश	उत्पादक का नाम	राशि (रु. प्रति कि.ग्रा.)	राशि (रु. प्रति कि.ग्रा.)
1	2	3	4	5
1.	जापान	असारी कैमिकल इण्डस्ट्रीज लिमि.	81.36	7.63
		मित्सुबिसी रेयन कं. लिमि.	79.57	4.60
		टोयोबो कं. लिमि.	77.09	2.69
		अन्य कोई निर्यातक	81.36	7.63
2.	स्पेन	कोई भी निर्यातक	82.00	14.14
3.	पुर्तगाल	कोई भी निर्यातक	74.22	4.97
4.	इटली	कोई भी निर्यातक	81.12	10.66

56. इस प्रयोजन के लिए आयातों की पहुंच कीमत सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमा-शुल्क विभाग द्वारा तय की गई निर्धारण योग्य कीमत होगी और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख तथा 9 तथा 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी शुल्क अभ्रम शामिल होंगे।

57. उपर्युक्त के अधीन प्राधिकारी दिनांक 20.10.1998 के प्रारंभिक जांच-परिणाम को पुष्टि करते हैं।

58. उक्त अधिनियम के अनुसार इस आदेश के खिलाफ सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा म्बर्ण (नियंत्रण) अर्थात्तीय व्यापारिकरण के नाम अपील की जा सकती है।

रत्न विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं उपायुक्त

MINISTRY OF COMMERCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 1998

FINAL FINDINGS

Sub: Anti-dumping investigation concerning import of Acrylic Fibre from Japan, Portugal, Spain and Italy— Final Findings.

32/1/97-ADD Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for determination of injury) Rules, 1995 thereof.

A PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed subsequent to the preliminary findings :

(a) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified preliminary findings vide notification dated the 20.10.98 with regard to anti-dumping investigations concerning import of Acrylic Fibre from Japan, Portugal, Spain & Italy and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;

(b) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter;

(c) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of the Japan, Portugal, Spain and Italy in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings;

(d) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 3.12.98. All parties presenting views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any ;

(e) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted and arguments made by various interested parties. All parties who made request for inspection, in writing, were allowed to inspect the public file ;

(f) Arguments raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties have been appropriately dealt in the preliminary findings and/or these findings;

(g) In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts/basic considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on same has been duly considered in these findings;

(h)****in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product involved is Acrylic Fibre both in shrinkable and non-shrinkable form ranging from 1.5 denier to 8.0 denier and is classified under custom code 5501.30 and 5503 30 of Custom Tariff Act 1975. Acrylic Fibre is an economical substitute of wool. Acrylic Fibre is produced either through wet technology or dry technology. Acrylic Fibre has application in day to day life i.e. apparel, household products and some industrial uses.

Argument by petitioner

3. Petitioner has argued that tow and top are acrylic Fibre only. In case the Fibre has 2.0 meter length, it is called tow. In case it has variable length of less than 2.0 meter, it is called staple Fibre. Both tow and staple can be used by a consumer in the same plant for the same purpose and thus staple Fibre and tow have the same use. It is also argued by the petitioner that in the earlier case of anti-dumping investigation from US, Korea and Thailand, duties were levied also on tow, top and staple. The gazette notification issued by the Designated Authority and Ministry of Finance are public documents known to entire industry. Pleading at this stage that the information furnished by a particular exporter is only for staple Fibre and does not includes tow clearly shows lack of understanding on the part of exporters. Thus tow and top are included under the scope of investigation and Designated Authority should confirm it preliminary findings with regard to scope of present investigations.

Argument by exporter/importer:

4. It is argued by exporter/importer that the recommendation of Designated Authority with regard to imposition of duty on "Tow" is without jurisdiction, arbitrary and bad in law. The petitioner had petitioned for imposition of anti-dumping duty on acrylic Fibre under customs code 5503 30 and initiation notification was issued accordingly, Tow is a distinct commodity which falls under tariff entry 5501.30. Tow was not a subject matter of investigation. By not initiating an investigation against tow and imposing duty subsequently on Tow, the Authority had not given a chance to submit necessary information on

Tow. Similar is the case with top. Hence these should be excluded from the scope of investigation.

Authority Position

5. The Authority refer to circular No. 29 CBEC dt. 23rd April, 98 issued by Govt. wherein it was mentioned that on the basis of report that acrylic tow and top are sought to be cleared without payment of anti-dumping duty, Board in consultation with MOC has decided that acrylic top and acrylic tow are also leviable to anti-dumping duty and past clearance if any may also be reviewed in light of this clarification.

6. The Authority also notes that Tow is classified at custom tariff entry No. 5501.30 and Acrylic Fibre is classified at entry No. 5503.30, At the time of initiation, it was also indicated in the notification that the classification is indicative only and not binding on the scope of investigation. Tow can be converted into acrylic Fibre by cutting the tow. Even some of the exporters have included information on tow, while responding to the questionnaire and subsequent submission without disputing that tow is a distinct product. Further the Authority had recommended anti-dumping duties on tow, top and staple Fibre, the same were levied by Central Government. In view of this, the Authority considers it appropriate to recommend duties on tow, top and staple Fibre.

Argument raised

7. M/s Asahi, Japan has requested that in case the Authority decides to include the "tow" within the scope of investigation, the information submitted by them subsequent to verification and subsequent to preliminary findings should be considered for the determination of dumping margin.

Authority Position

8. With regard to argument of Asahi to include tow and top for determination of dumping margin, the Authority notes that the exporter has not furnished information with regard to tow and top at the time of initiation, nor the same was made available to the investigating team at the time of verification. The information furnished subsequent to the preliminary findings is unverified. Further, accepting information at this stage may not be fair to the other cooperative exporters from the subject countries and the petitioners. The exporter is, however, at a liberty to file information separately and request separate assessment.

Argument raised

9. Modacrylic should be excluded from the scope of investigation as it does not answer to the description of product under consideration. This Fibre is composed of about 50% of acrylonitrile units by weight whereas acrylic Fibre is a co-polymer of more than 85% of acrylonitrile. Due to unique feature of flame retardancy, mod acrylic Fibre can not be substituted by acrylic Fibre.

Authority Position

10. The authority agrees to the argument of exporter. The petitioner has not disputed the claim of exporter. The petitioner has also agreed that Indian Industry does not currently to manufacture modacrylic (self extinguishable) Fibre. In view of this the Authority excludes the modacrylic Fibre from the scope of investigations.

C. LIKE ARTICLE

11. Acrylic Fibre produced and sold by the domestic industry has characteristics closely resembling acrylic Fibre imported from Japan, Portugal, Spain and Italy and are treated as Like articles as per the definition in the anti-dumping rules.

Argument by Exporter/Importer

12. The arguments raised by the exporters and importers on like article are as under:

(a) GK and K 75 are specialty Fibres having a special proprietary technology which is not available in India. The Process of manufacture is different in GK and K 75 type of specialty Fibre. The end uses can not be substituted. These Fibres should be excluded from the scope of investigation.

(b) L-2 Low shrink, V 86 and V 85 modified special surface finish, conjugate/bicomponent Fibre, H 525 are other specialty Fibre which should be excluded from scope of investigation, being not Like article.

Argument by the petitioner :

13. Petitioner has argued that claim of the exporter about exclusion of specialty Fibre is not correct as the Indian industry has capability, technology, plant and equipment to produce all type of Fibres. Indian industry has license to manufacture all types of Acrylic Fibre, except for modacrylic (self-extinguishable), V76 Mohair and V86. IPCL have been making all type of Fibre including conjugate Fibres. Consolidated Fibre & Chemicals is licensed to produce all type of Fibre which Exlan-Toyobo can produce. Pasupati Acrylon is producing Fibre with license from Snea of Italy. Indian Acrylics is producing Fibre by Dupont Technology from USA and produce all forms of Fibres.

Authority Position

14. With regard to exclusion of specialty Fibre and conjugate Fibre, the Authority notes that the claim of the exporters that the domestic industry does not have technology and plant & equipment to produce these Fibres is factually incorrect. IPCL has both the technology and plant & equipment. Further, it is not denied that IPCL has been producing these fibres. Whether these are produced using wet process technology or dry process technology is also of little consequence as the differences arising out of the same, if any, have also not been substantiated. It is not necessary that each of the Indian producers should be making such fibres. The claim of the exporters is liable to

be rejected on this account alone. Notwithstanding this fact, the Authority notes that other Fibres being produced by the domestic industry and those special fibres being imported from the subject countries have also been used for the same purpose by the consumers. Moreover, the exporters have not been able to substantiate their claim that these fibres are special fibres based on the pricing of these goods vis-à-vis ordinary Fibre. The details of the prices at which goods have been exported to India does not establish the claim of the exporters that these are special Fibre, as the export price of ordinary Fibre and special Fibres are in the same region. The Authority notes that in case these are special fibres, these should have attracted higher prices in the Indian market. The Authority therefore hold that acrylic Fibre produced and sold by the domestic industry has characteristics closely resembling to the acrylic Fibres imported from Japan, Portugal, Spain and Italy and, therefore, may be treated as like articles within the meaning of rules supra.

D. DOMESTIC INDUSTRY

15. The petition is jointly filed by M/s Indian Acrylics Ltd., Chandigarh, Pasupati Acrylon Ltd., New Delhi, J.K. Synthetics Ltd., New Delhi and Consolidated Fibre and Chemicals Ltd., Calcutta. It is claimed by the petitioner that Indian Petrochemical Ltd., having their plant at Vadodra is the other company producing acrylic Fibre. Thus, it is claimed that these are the five units who produce acrylic Fibre having a combined capacity of 1,02,000 MT. The total production of acrylic Fibre in 1996-97 is stated as 79000 MT and the production of petitioner companies is 61187 MT. The petition has the support of the "Forum of Acrylic Fibre manufactures" and all the five companies are members of the Forum of Acrylic Fibre manufacturers. Thus the petitioner accounts for more than 25% of domestic production and therefore have a standing to file a petition on behalf of domestic industry under the rules. None of the interested parties have raised any argument in respect of the standing of the petitioners to file the petition. The Authority thus confirms the preliminary findings that petitioner accounts for more than 25% of domestic production and therefore have a standing to file a petition on behalf of domestic industry under the rules.

E. DUMPING

Argument of exporter

16. M/s Kaneka Corpn, Mitsui & Co. and Kanematsu Corpn, Japan had responded after the last date of submission by exporter. These were not considered in the preliminary findings. The exporter has requested that these may be considered now.

Authority's Position

17. The Authority observes that Kaneka Corpn, has claimed that they produce only Modacrylic Fibre bearing Kanecaron Brand and Protex brand and export to India through Mitsui & Co. and Kanematsu Corpn.. It is also claimed that as per best to their knowledge, there is no production of Modacrylic Fibre or like product in India and therefore there must be no injury to domestic industry. The Authority has already hold in para on "product under consideration" that Modacrylic Fibre (self extinguishable) be excluded

from the scope of investigations, and therefore the Authority has not examined the claim of above exporters relating to modacrylic Fibre.

Argument by petitioner

18. The dumping margin assessed by Designated Authority are significantly lower as compared to the information available with petitioner.

Authority Position

19. The Authority has given the methodology of calculating the dumping margin in preliminary findings. The dumping margin are based on facts and figures submitted by the exporters which has been verified by Authority to the extent necessary. The petitioner has neither disputed the methodology adopted by the Authority to calculate the dumping margin nor the facts and figures available in public file which were submitted by exporters. Thus the argument of the petitioner that dumping margin are significantly lower as compared to information available with petitioner is too generic in nature and is not substantiated with facts.

Argument raised

20. Calculation of dumping margin should be done grade/denier wise by the Designated Authority as done by Designated Authority in other case of import of acrylic Fibre from USA.

Authority Position

21. The Authority hold at Para 11 of the preliminary findings that on the basis of the facts available with the Authority, it is observed that the various deniers of acrylic Fibres do not display any significant difference in terms of the cost or prices and are in the same range. Moreover, there is a considerable amount of substitutability among the different varieties and therefore the Authority grouped all Fibres (described as product under consideration) for these investigations. The Authority notes that none of the interested parties has disputed to the observation of the Authority in Para 11 of the preliminary findings. None of the interested party has substantiated that different denier displays any significant difference in terms of cost or price or whether they are not in same range or that there is no substitutability among the different varieties. Therefore the Authority hold its earlier decision and has grouped all Fibre (described a product under consideration) for these investigation.

Argument raised

22. The exporters have argued that while determining normal value and export price certain adjustments have not been allowed by Authority in the preliminary findings. These should be allowed. On this the petitioner has argued that Authority has correctly disallowed the adjustments.

Authority Position

23. The Authority has dealt with adjustments in preliminary findings in detail. There is no dispute by any interested party over the various adjustment allowed by Authority. However, the exporters have argued over the adjustment which have been disallowed. While disallowing the adjustment, the Authority had explained the reasons for disallowing the claims.

24. Exporter wise claims are re-considered as under :-

I. Asahi Chemical Industries Ltd., Japan

25. Adjustment on account of storage cost which is claimed on the basis of inventories held by the company was disallowed in the preliminary findings. The exporter clarified subsequent to the preliminary findings that the storage costs is warehousing costs for storage of goods before they are sold in the domestic market. These costs are paid to outside warehousing companies. Goods are sold to different customers from different warehouses. The Authority has adopted a consistent practice to disallow any expenses of this nature. In view of the same, the Authority considers it appropriate to disallow any expenses on this account. Since the exports from Japan were in Yen, the exporter has claimed that the Authority should adopt exchange considering Yen to Rs. in stead of Yen to US \$ and US \$ to Rs. It is observed that the Authority had adopted Yen to US \$ and US \$ to Rs. at the time of preliminary findings, as the exporters had furnished information accordingly. However, since the exporters have now requested for Yen to Rs. conversion, the Authority has adopted the same.

26. In the preliminary findings, the Authority disallowed the claim made on account of discounts based on turnover and end use as the incidence of such discounts/rebate is not ascertainable at the time of pricing decisions. The Authority notes that while it is not established that both amounts payable are determined and agreed to at the time of entering into the contract. In fact only the terms and conditions under which such amounts are payable are known at the time of entering into contract. The actual amounts payable are known only after the completion of relevant period and largely depends on the fulfillment of certain conditions during the period. The very fact that only those customers who fulfil these conditions are eligible to receive the amounts establishes that the total amount payable by the company is not known to the company at the beginning of the period, which is an essential condition for claiming price adjustment on account of differences in the expenses in the two market. In view of this, the claim is not allowed.

27. In view of this, the Authority re-determined the dumping margin, and the same comes to 18.26 % of export price. Since the Authority has considered Yen to Rs. exchange in case of Asahi, it is considered appropriate to adopt the same exchange rates for the other producers from Japan also. Accordingly, the dumping margin were re-determined in case of Mitsubishi and Toyobo and the revised dumping margins come to 11.3 % and 5.92 % respectively.

II. Monte Fibre Italy

28. The determination of dumping in case of Monte Fibre is as under:

(a) Prompt payment and quantity discount at 2% is claimed on estimates. It is claimed that it varies from 1% to 4% and therefore an average of 2% is used to claim the deduction. The Authority disallowed the claim as it was claimed on estimated. It is now requested that as the minimum discount was

1%, it should be allowed. The Authority agrees with the argument and prompt payment and quantity discount at the minimum i.e. 1% is allowed.

(b) The claim on account of R&D, promotion and advertisement, was disallowed as the Authority did not find justification to allow these expenses in the absence of evidence to establish that the benefit of these activities have been restricted to domestic sales only. The exporter has requested to reconsider the claim on the basis that R&D cost, technical services and promotion, as these are only in respect of the Fibres sold in the domestic market. The Authority notes that exporter has not submitted any additional evidence and the claim is disallowed due to reasons already given in the preliminary findings.

(c) The exporter had requested, during verification, to allow a deduction equal to weighted average commission paid to Indian agent, while determining the normal value. The Authority had disallowed the claim in the absence of substantiation by the exporter even at the time of verification visit. They have request to reconsider the claim on the basis that export to India are through agents whereas sales in the domestic market was on direct basis and thus there is a difference in the level of trade. The Authority notes that the exporter has not submitted any additional evidence and thus the claim is disallowed due to reasons already given in the preliminary findings.

29. In view of above, the dumping margin is revised to 22.90% of export price.

III. Courtlauds Espana, SA, Spain

30. The exporter had requested, during verification, to allow a deduction equal to weighted average commission paid to Indian agent, while determining the normal value. The Authority had disallowed the claim in the absence of substantiation by the exporter even at the time of verification visit. The exporter has now requested to reconsider the claim on the basis that exports to India are through agents whereas sales in domestic market was on direct basis and thus there is a difference in the level of trade. The Authority notes that the exporter has not submitted any additional evidence and thus the claim is disallowed due to reasons already given in the preliminary findings. In view of this, there is no change in the dumping margin given in preliminary findings.

IV. Fisipe Portugal

31. The claim on storage charges was disallowed. The claim was made on account of storage cost on the basis of excess inventory holding by the company. The exporter has requested to reconsider the claim as no reason has been given by Authority for rejecting the claim. The Authority notes that the claim was made in respect of excess inventory which the exporter is keeping in respect of sales in domestic market. The claim is on the basis of estimates and is, therefore, disallowed. In view of this, there is no change in the dumping margin as given in the preliminary findings.

32. Except for the foregoing the Authority confirm preliminary findings with regard to dumping and dumping margin in respect of other exporters from the subject countries.

F. INJURY AND CAUSAL LINK

33. Petitioner Argument: The petitioner has suffered material injury due to:
- Increase in imports from subject countries
 - Increase in imports in absolute terms from all countries
 - The increase in market share of imports and consequent decline in market share of petitioner
 - Losses in spite of more than 100% capacity utilization.
 - Increase in closing stock
 - Price undercutting by imports
 - Inability to raise funds
 - Inability to take up R&D activities to develop new applications of Fibre.

Arguments by Exporter/Importer

34. Domestic industry has not suffered any injury in view of the fact that -
- the production, capacity utilization, sales have increased during period of investigation,
 - selling prices have come down due to reduction in cost of production,
 - profitability of the petitioners has increased and loss making units have started making profits,
 - Plans for expansion have been implemented,
 - decline in market share is due to increase in demand which domestic industry is unable to produce,
 - Alleged increase in inventories is one of the lowest in the world,
 - J K Synthetics should be excluded for the purpose of injury analysis as they have internal problems and has nothing to do with the alleged dumping,
 - The price depression is exclusively attributable to imports from other countries.

AUTHORITY POSITION

35. It is appreciated that the production, capacity utilization, sales volumes, etc. of domestic industry have increased. The Authority, however, notes that all relevant parameters affecting domestic industry need not establish injury. As noted by the Authority in the para L relating to conclusion on injury in the preliminary findings also, material injury to the domestic industry is evidenced from the factors such as increase in quantum of imports from the subject countries in absolute terms and relative to consumption of Acrylic Fibre in India, decline in the market share of the petitioner companies, inability of the domestic industry to sell at fair price, undercutting of the selling prices of the domestic industry by the imports from subject countries, increase in the closing stock of domestic industry, losses being incurred by the domestic industry, etc. With regard to the reduction in selling prices due to decline in the prices of raw material, the Authority notes that though prices of raw material might have resulted in decline in the selling prices, yet the fact that the domestic industry was prevented from earning reasonable profit has not been disputed. Since the Authority has excluded J K Synthetics while arriving at the fair selling price for the domestic industry, the parameters affecting J K Synthetics deserves to be ignored.

36. In view of the above and in the light of the arguments raised by all interested parties, the Authority observes that the domestic industry has suffered material injury. Further, the material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports.

G. OTHER ARGUMENTS

Arguments raised

37. The Designated Authority has initiated investigation against Japan, Portugal, Spain & Italy. The Designated Authority has not initiated investigation against European Union as a whole as requested by petitioner. The Designated Authority has neither explained reasons in the initiation notification nor in the preliminary findings for not initiating case against European Union. The imposition of anti-dumping duty against any member country of European Union can not be effective without imposition of anti-dumping duty against European Union as a whole. There is no custom barriers in the European Union. Malaysia and Indonesia has imposed duties against European Union as whole.

Authority Position

38. The Authority decided to initiate the investigation against the countries which were named in the petition and against which specific information on normal value and export price were submitted. It is also observed that in the petition filed, the petitioner had requested to initiate investigation against EU as whole also. However vide their letter dt. 2/12/97, the petitioner inter-alia requested as under :-

“ The investigation into the alleged dumping may please be initiated against the named countries individually rather than collectively. You may consider our petition accordingly and initiate investigation proceedings against Japan, Portugal Spain & Italy.”

39. The Authority had accordingly initiated the investigation against the specific countries. Thus the argument of the petitioner that they requested to initiate investigation against EU as a whole is factually incorrect. The Authority is not in a position to consider the request for inclusion of EU at this late stage.

Argument raised

40. Injury is more severe in the post investigation period due to increase in imports, increase in closing stock and decline in sales realizations.

Authority Position

41. The Authority do not take into account the injury if any, during the post investigation as the other interested parties are not given proper opportunities to comment upon such injury incurred in the post investigation period.

Argument raised

42. The Authority should clarify in the final findings that even though the invoice is from a trading house, the anti-dumping duty be levied based upon the

manufacturer of product and not on the trading house in whose name the invoice appears.

Authority position

43. With regard to separate assessment of the trading houses, the Authority notes that by virtue of very nature of these entities they are free to export goods of any producer, no mechanism can be evolved which can establish linkage between the purchases and sales made by these trading houses. It is largely the practice of the investigating authorities that only the producers are assessed for separate duties. Moreover, the trading houses are not deprived of business by not being assessed separately.

Argument raised:

44. As represented by the exporters fixing reference price is contrary to the anti-dumping rule that anti-dumping duty shall not be greater than the injury margin and fixing of anti-dumping duty with reference to a reference price in the present case is discriminatory when compared to the exporters from other countries against whom "fixed duties" were imposed. It has been argued by the petitioner that the duties should be recommended on variable basis, as was done at the time of preliminary findings. It has also been argued by the exporters that the recommendations of Authority should be for a minimum price subject to a maximum duty equal to dumping margin determined for each exporter.

Authority's Position

45. The Authority considers it appropriate to recommend anti-dumping duty on variable basis having reference price with a condition of certain minimum duties. The Authority does not consider that the duties recommended are discriminatory when compared to the exporters from other countries.

46. It has not been established by any interested party how the recommendations of variable duties with provision for certain minimum amounts are inconsistent with the provisions of the Rules. Further, these minimum duties are required to be recommended so as to avoid any possible circumvention. In case it is felt by an exporter that the current dumping margin is lower than the duties being collected, an exporter can request review in accordance with the Rules.

Argument raised

47. It is not correct and proper to put at par wet spun and dry spun fibres as production, technology, processing and end use are altogether different.

Authority Position

48. The Authority notes that there are two well acknowledged technology for production of acrylic fibre – the wet spun and the dry spun. None of the interested parties have been able to establish with evidence any significant variation in the fibre produced by the two technology. Moreover, domestic industry produces fibres using both the technologies and the fibres produced

using both the technologies are being consumed interchangeably by the consumers.

Argument raised

49. The DGCIS statistics show that the prices of imports from the countries which are not dumping are lower than the price of the allegedly dumped imports. Thus the imports from the other countries at a lower price had caused the price under cutting/depression if any during the period of investigation. The quantity of such low price imports is also significant.

Authority Position

50. The Authority observed that total imports of acrylic fibre during the period of investigation were 21114 MT. Out of this, the imports from Japan, Portugal, Spain & Italy who are allegedly dumping in this petition were 9548 MT. Out of the remaining 11566 MT, the imports from USA, Thailand & Korea were 8727 MT against whom the Authority had initiated anti-dumping investigations. These imports from USA, Thailand & Korea were also at the alleged dumped price. Thus majority of the imports were at the allegedly dumped price during the period of investigation and the argument raised in this regard is factually incorrect.

51. It is observed that some exporters have represented that they had not exported acrylic fibre during the period of investigation and therefore, no anti-dumping duty be levied on their product/export. The Authority notes that since these exporters have not exported during the period of investigation, they attract rule 22 and may accordingly request for separate assessment.

Argument raised

52. Embassy of Spain, New Delhi has claimed that Spain should be exempted from these anti-dumping measures due to level of the Spanish exports. It is claimed that the Spanish exports during the period of investigation appear to be nil.

Authority Position

53. The Authority notes that according to import statistics and information furnished by M/s Courtlauds Spain, Spain has exported acrylic fibre during the period of investigation and thus the claim of the Embassy is not factually correct.

FINAL FINDINGS

54. The Authority, after considering the foregoing, concludes that:

- (a) Acrylic fibre has been exported from Japan, Portugal, Spain and Italy has been exported to India below its normal value resulting in dumping of acrylic fibre;
- (b) the domestic industry has suffered material injury;
- (c) the causal link between dumping and injury is established.

55. The Authority confirms the preliminary findings with regard to imposition of Anti-dumping duty and recommends imposition of definitive anti-dumping duties on all imports of acrylic fibre falling under custom sub-heading nos. 5501.30 and 5503.30 of the Customs Tariff Act as specified under para relating to product under consideration originating in or exported from Japan, Spain, Portugal and Italy. The anti-dumping duty shall be the difference

between the amount mentioned in column 4 and the landed price of imports per kg., subject to a minimum of anti-dumping duty per kg. as mentioned in column 5 below.

SN 1	Country 2	Name of the producer 3	Amount (Rs. per kg.) 4	Amount (Rs. per kg. 5
1.	Japan	Asahi Chemical Industries Ltd. Mitsubishi Rayon Co. Ltd. Toyobo Co., Ltd. Any other exporter	81.36 79.57 77.09 81.36	7.63 4.69 2.69 7.63
2.	Spain	any exporter	82.00	14.14
3.	Portugal	any exporter	74.22	4.97
4.	Italy	any exporter	81.12	10.66

56. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

57. Subject to above, the Authority confirms the preliminary findings dated 20.10.1998.

58. An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act Supra.

RATHI VINAY JHA. Designated Authority & Addl Secy.